खंड १८ नंबर २ अप्रैल २०२२

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस में आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) पर विशेष सप्ताह

विकास साझेदारी के 75 वर्ष–अनेकता, विविधता और सामूहिक प्रगति के प्रति समर्पण की गाथा पर प्रदर्शनी

भारत की माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी आरआईएस द्वारा मनाए जा रहे एकेएएम में अपने उद्‌गार प्रकट कर रही हैं।

भारत 'विकास सहयोग' के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है, क्योंकि उसके द्वारा तीसरी दुनिया के देशों (यानी ग्लोबल साउथ) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता के साथ– साथ वित्तीय सहायता बिना किसी शर्त के और *'वसुधैव कुटुम्बकम'* (समूचा विश्व एक परिवार है) के वैदिक मंत्र की भावना के साथ उपलब्ध करायी जाती है। यह उद्‌गार माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 21 फरवरी, 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अंतर्गत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय के एकेएएम कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 75 वर्षों में भारत की ओर से की गई विकास सहयोग संबंधी पहलों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। आज़ादी के 75 वर्षों का जश्न तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव उपयुक्त रूप से मनाने के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के बाद इसी विषय पर सप्ताह भर चलने वाली एक प्रदर्शनी प्रारंभ की गई।

रिपोर्ट अनावरण करने के अवसर पर श्रीमती लेखी ने कहा, ''हम (भारत) इस आशय (विकास सहयोग में) से अग्रणी (विश्व में) है, लेकिन हम अपने महत्व को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। हमारी (भारत की) अच्छाई और कोविड–19 महामारी के दौरान हमारी ओर से विश्व को टीकाकरण और चिकित्सा सहायता समेत उपलब्ध करायी गई मदद का दाम कभी चुकाया नहीं जा सकता, जिसका उत्सव इस प्रदर्शनी के माध्यम से मनाया जा रहा है।

इस अवसर पर आरआईएस के अध्यक्ष

...शेष पृष्ठ 2 पर जारी

भारत की माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन कर रही हैं।

डॉ. मोहन कुमार ने कहा कि भारत की ओर से दिया जाने वाला विकास सहयोग सहायता प्राप्तकर्ता देशों की प्राथमिकताओं पर आधारित और पूरी तरह मांग से प्रेरित है। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि आरआईएस ने कड़ी मेहनत करके सभी मंत्रालयों की वार्षिक रिर्पोटों से 1947 से 2022 तक की जानकारी का संकलन किया है। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता केवल धन के संदर्भ में ही नहीं रही, बल्कि 'सदर्न कलेक्टिव', 'जलवायु न्याय', 'अवैध वित्तीय प्रवाह', 'प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र', 'शांति सेना' और 'लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) जैसी अवधारणाओं के रूप में भी रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में विश्व की सहायता करने के लिए नेट–ज़ीरो स्टेटस हासिल करने की बात कही थी। प्रो. चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी संस्थाओं के गठन में भी सहायता की है। भारत ने 1952 में नेपाल में 'भारत सहायता मिशन' की भी स्थापना की और बाद में इसका नाम बदलकर 'भारतीय सहयोग मिशन' करने का फैसला लिया गया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि सहायता का दृष्टिकोण इस्तेमाल करने की बजाए, देने का सिद्धांत विकास सहयोग पर आधारित होना चाहिए।

रिपोर्ट के प्रमुख अंश

- वर्ष 1947 से 2022 तक भारत द्वारा प्रदान की गई विकास सहायता की मात्रा 127 बिलियन डॉलर रही।
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) सहित कई पहलों के माध्यम से विकासशील देशों के अन्य देशों के 350,000 लोगों को प्रशिक्षित किया।
- भारत द्वारा लगभग 31 बिलियन डॉलर राशि की ऋण सहायता प्रदान की गई है, और इसका लगभग आधा भाग पड़ोसी देशों को दिया गया।
- कोविड–19 के प्रकोप के बाद, भारत ने 90 से अधिक देशों को टीके और लगभग 100 देशों को 4 बिलियन डॉलर का सहायता अनुदान प्रदान किया है।

आरआईएस की रिपोर्ट के अनुसार गरीब देशों को भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत का पूर्वनिश्चित शुल्क 7 बिलियन डॉलर का था। आलोच्य अवधि के दौरान कृषि उपकरणों के वितरण सहित भारत द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति संबंधी सहायता भी 7 बिलियन डॉलर रही। संयोग से, आरआईएस में विकास सहयोग के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के प्रति समर्पित एक मंच– भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) है, जो अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग परिदृश्य की पृष्ठभूमि में भारत के अपने अनुभवों का उपयोग करने की दिशा में प्रयासरत है। यह विदेश मंत्रालय, अकादमिक और नागरिक समाज संगठनों के विकास भागीदारी प्रशासन की एक त्रिपक्षीय पहल है।

शुरुआत से ही मंत्री महोदया ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य देशों के साथ भारत के आधिकारिक संपर्कों में यह रिपोर्ट उपयोगी साबित होगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की समस्त सूचनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ■

भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ राज कुमार रंजन सिंह प्रदर्शनी में प्रतिभागियों से मुलाकात कर रहे हैं।

"भारत की विकास साझेदारी के 75 वर्षों की रूपरेखा: नई संभावनाओं की तलाश और उभरती चुनौतियों से निपटना" विषय पर पैनल परिचर्चा

आज़ादी के 75वें वर्ष का समारोह तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) को उपयुक्त रूप से मनाने के लिए आरआइ.ंएस की ओर से 21–27 फरवरी, 2022 के दौरान एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रमुख सार्वजनिक और निजी इकाइयों, नागरिक समाज संगठनों और सामाजिक उद्मियों को साथ लाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विविध देशों के साथ भारत की विकास पहलों को दर्शाया गया।

इस अवसर पर आरआईएस ने 25 फरवरी, 2022 को "भारत की विकास साझेदारी के 75 वर्षों की रूपरेखा : नई संभावनाओं की तलाश और उभरती चुनौतियों से निपटना" विषय पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया। डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने इसमें स्वागत भाषण दिया और राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने इसकी अध्यक्षता की। इस परिचर्चा में : श्री प्रभात कुमार, अपर सचिव (डीपीए), विदेश मंत्रालय; डॉ सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), संस्कृति मंत्रालय, श्री डेविड रसकिन्हा, पूर्व प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक; डॉ रुचिता बेरी, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, द मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी–आईडीएसए); डॉ एस के वार्ष्णेय, सलाहकार/वैज्ञानिक जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग; श्री एस कुप्पुस्वामी, सलाहकार–समूह वित्त और विशेष परियोजनाएं, शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड और श्री चंद्र भूषण, अध्यक्ष और सीईओ, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (आई फॉरेस्ट) ने भाग लिया। डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

बाएं से दाएं: डॉ. सब्यसाची साहा, श्री चंद्र भूषण, श्री डेविड रसकिन्हा, श्री प्रभात कुमार, राजदूत अमर सिन्हा, डॉ सच्चिदानंद जोशी, डॉ रुचिता बेरी और श्री एस कुप्पुस्वामी

सत्त विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्यों पर अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ राज कुमार रंजन सिंह, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के शोधार्थियों के साथ बातचीत करते हुए।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर पूर्वोत्तर के युवा शोधार्थियों के लिए दो सप्ताह के अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण आरआईएस और नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एडवोकेसी फाउंडेशन (एनईटीआरए) के प्रमुख कार्यक्रम के तहत आरआईएस, नई दिल्ली में 14–18 मार्च, 2022 के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 15 शोधार्थी शामिल हुए।

एफआईडीसी और प्रिया के अध्यक्ष डॉ राजेश टंडन ने अपने उद्‍घाटन भाषण में 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के परिप्रेक्ष्य में एसडीजी का स्थानीयकरण' के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एसडीजी की परिकल्पना मौलिकता और प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए मूलभूत ज्ञान और आधुनिक तकनीक को जोड़ने के लिए मूल निवासियों को साथ जोड़कर और उनके साथ काम करके ही परिपूर्ण की जा सकती है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपना शोध कार्य अपने लोगों या अपने समुदाय को समर्पित करने का आग्रह किया।

आरआईएस में विजिटिंग फेलो प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती ने सतत विकास लक्ष्यों(एसडीजी) पर संक्षिप्त भाषण तथा सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में दो सप्ताह के अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम के महत्व का वर्णन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने आरआईएस और एनईटीआरए के सहयोग के महत्व तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में समस्त 17 एसडीजी लाने या हासिल करने के लिए उनके द्वारा मिल–जुलकर किए जाने वाले कार्यों का भी उल्लेख किया। प्रो. चक्रवर्ती ने अपनी प्रस्तुति में पूर्वोत्तर भारत में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दों को भी उठाया।

माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने भी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में एसडीजी हासिल करने के बारे में प्रतिभागियों के प्रश्नों और सुझावों को जाना। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि क्षेत्र की मौलिकता को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं को आधुनिक ज्ञान के साथ एकीकृत करके एसडीजी हासिल किए जाने चाहिए। प्रो. एस के मोहंती, वरिष्ठ प्रोफेसर, आरआईएस और डॉ. सुमित सेठ, संयुक्त सचिव, नीतिगत योजना एवं अनुसंधान, विदेश मंत्रालय भी इस बातचीत में सम्मिलित हुए। एसडीजी–शोधार्थियों के साथ बातचीत करते हुए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने सभी प्रतिभागियों से जमीनी स्तर पर जाने और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों का पता लगाने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न नीति निर्माताओं को स्थानीय लोगों के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने 'भारत का विकास सहयोग : 17 एसडीजी के संबंध में क्रॉस बॉर्डर स्पेक्ट्रम' के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि शोधकर्ता को अपने क्षेत्र में मौजूद बुनियादी समस्याओं का पता लगाने और उनके उपयुक्त सर्वोत्तम संभावित विकल्पों को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय समुदाय से जुड़ी समस्याओं को हल करने के तरीकों का पता लगाने की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत तो इस बात की है कि उन समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाए।

वक्ताओं में, आरआईएस के फेलो श्री शुभोमॉय भट्टाचार्य ने ऊर्जा सुरक्षा (एसडीजी–7) और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से नवीकरणीय स्रोत में परिवर्तन के जोखिम और लाभ के कारक को समझने की अनिवार्यता के बारे में चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशिष्ट विकल्पों की पहचान करने की आवश्यकता की ओर इंगित किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार एसडीजी–अनुसंधान विद्वानों के साथ।

आरआईएस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ प्रियदर्शी दाश ने एसडीजी के वित्त पोषण से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने घरेलू और विदेशी संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाने के महत्व पर भी बल दिया।

सबके लिए निरंतर स्वास्थ्य (एसडीजी–3) से संबंधित मुद्दों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर, आरआईएस और एनआईपीओ के अध्यक्ष टी.सी. जेम्स ने स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य और निरंतर स्वास्थ्य देखरेख के बारे में विस्तार से बताया। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी के लिए निरंतर स्वास्थ्य हासिल करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों की सहायता की आवश्यकता है।

एनआईयूए में वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ पूर्वा ने अपनी प्रस्तुति में इस बात की ओर संकेत किया कि सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को वैश्विक ढांचे के समानांतर लाना आसान नहीं है, इसलिए हमें शहर के स्तर (एसडीजी–11) पर जाने और इन संकेतकों को विकसित करने तथा उन संकेतकों को समझने की आवश्यकता है।

आरआईएस में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू ने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे एसडीजी–11 शहरीकरण की मौजूदा संरचना पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि मौजूदा सेटलमेंट हायरार्की (यानी आबादी या अन्य मापदंडों पर आधारित बस्तियों के पदानुक्रम) में सब कुछ बड़े शहरों में केंद्रित है, जो फ्रेमवर्क में चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने एक शहरी प्रवास रणनीति और बस्ती की रणनीति बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमारे पास एक ऐसी बस्ती संरचना होनी चाहिए जो पूरे क्षेत्र को एकीकृत कर सके।

महिलाओं–पुरुषों में समानता, एसडीजी–5 की व्याख्या करते हुए आरआईएस की डॉ बीना पांडे ने जोर देकर कहा कि गरीबी उन्मूलन, असमानता, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा तक सबकी पहुंच, अच्छे कार्यों और आर्थिक विकास जैसे अनेक अन्य एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण अनिवार्य पूर्व शर्त है।

प्रिया के निदेशक डॉ कौस्तुभ बंद्योपाध्याय ने समुदाय या राष्ट्र में किसी नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सीएसओ की मदद से हाशिए पर मौजूद लोगों और वंचितों की पहुंच उनके लिए बनाई गई सेवाओं तक संभव हो पाती हैं। उन्होंने साझेदारियां कायम करने के कारण और अपेक्षाकृत समकक्ष सामर्थ्य वाले संगठनों, स्पष्ट रूप से परिभाषित संगठनात्मक संरचना और एक–दूसरे के साथ काम करने की सभी भागीदारों की क्षमता में वृद्धि सहित सफल साझेदारी में योगदान देने वाले कारकों को रेखांकित किया।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, एनईटीआरए के संस्थापक डॉ जयंत चौधरी ने इस बारे में चर्चा की कि पूर्वोत्तर भारत में एसडीजी का स्थानीयकरण किस प्रकार किया जाए। डॉ. चौधरी ने विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण करने, पूर्वोत्तर भारत में मौजूदा स्थानीय स्तर के संस्थानों को मजबूत बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सीएसओ के महत्व पर भी बल दिया।

सभी प्रतिभागियों ने आरआईएस द्वारा 'मूल निवासी और भारत' विषय पर आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में, प्रतिभागियों ने एनईटी. आरए के बोर्ड मेंबर और अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग, आरजीयू के प्रोफेसर केसांग देगी के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का अगला चरण अप्रैल में क्षेत्रीय केंद्र, आईजीएनटीयू, मणिपुर में आयोजित किया जाएगा। ■

मूल निवासी और भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा

जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच और उनके लाभ साझा करने से संबंधित मुद्दों के संबंध में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा अपनाया गया रुख, भारतीय समाज के समृद्ध ताने–बाने की रचना करने वाले विभिन्न समूहों के लोगों को मूल निवासी मानने के उसके दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है।

हालांकि, मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं ने अलग–अलग स्थिति वाले लोगों, चाहे वे ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से अलग हों, को संदर्भित करने वाली उपयुक्त शब्दावलियों पर कुछ सवाल उठाए हैं। 'मूल निवासी' शब्द का उपयुक्त उपयोग तथा अधिकारों और विकास के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, यह कानूनी आख्यानों को कैसे आकार देता है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसी पृष्ठभूमि में, एफआईटीएम ने 16 मार्च 2022 को आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रोफेसर टी.सी. जेम्स द्वारा लिखित चर्चा पत्र *'इंटरनेशनल डिस्कशंस ऑन इन्डीजनस पीपुल एंड इंडिया'* पर आधारित एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुसू. चित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने की। इस पैनल चर्चा में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह, दिल्ली उच्च न्यायालय, श्रीमती भास्वती मुखर्जी, नीदरलैंड में भारत की पूर्व राजदूत और श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (एल एंड टी) विदेश मंत्रालय सम्मिलित हुईं।

माननीय राज्यसभा सदस्य और संसदीय राजभाषा समिति की उप–समिति के संयोजक श्री राम चंद्र जांगड़ा ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। ■

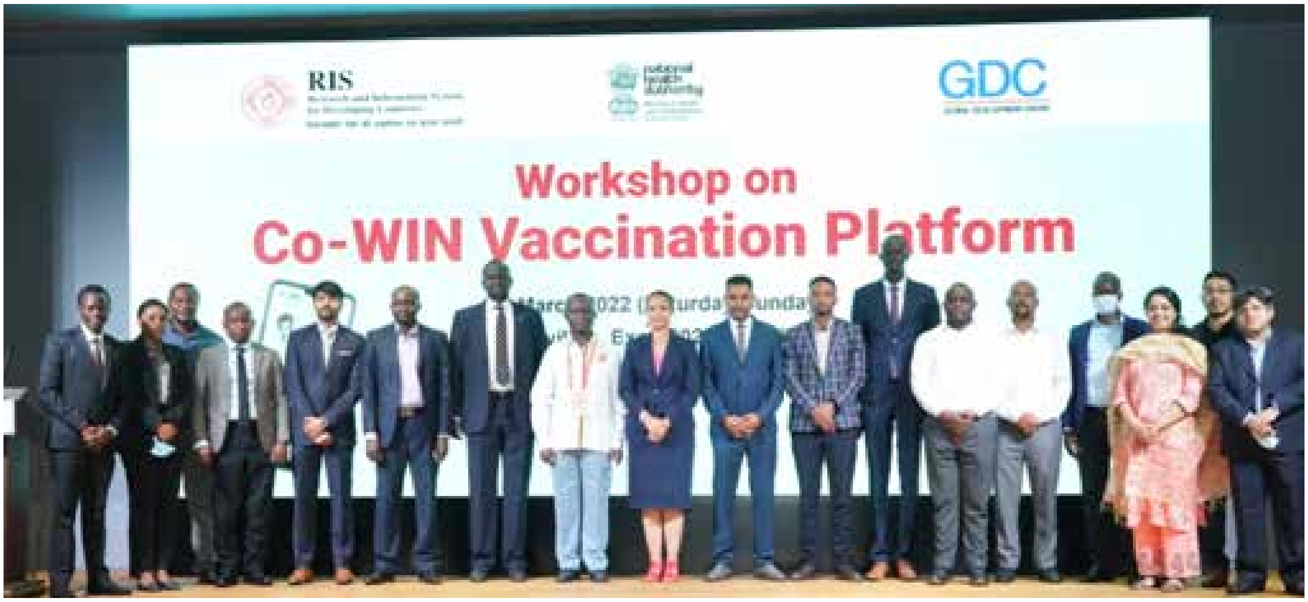

दुबई एक्सपो 2020 में प्रतिभागी।

भुगतान और टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर भारत के डिजिटल अनुभव का लाभ उठाना

आरआईएस के वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी) ने 5–6 मार्च 2022 को आयो. जित दुबई एक्सपो 2020 में भाग लिया। इस प्रदर्शनी ने एसडीजी का समर्थन करने के लिए देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग की मांग करने वाली वैश्विक समस्याओं के स्थायी समाधान तलाश. ने की आवश्यकता के बारे में वैचारिक आदान–प्रदान का अवसर दिया। इस अवसर पर,एक्सपो 2020, दुबई, यूएई में भारत के मंडप में जीडीसी ने एनपीसीआ. ई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआ. ईपीएल) के डिजिटल भुगतान समाध् ाान और को–विन डिजिटल टीकाकरण प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन करते हुए 'भुगतान और टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर भारत के डिजिटल अनुभव का लाभ उठाना' विषय पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। इन कार्यशालाओं में मलावी, जाम्बिया, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, मोज. ाम्बिक और रवांडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ अन्य देशों के मंडपों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जीडीसी ने मलावी, इथियोपिया और दक्षिण सूडान के देशों के साथ तीन तकनीकी द्विपक्षीय सत्रों में भी सहायता प्रदान की, जिसमें सीखने में महत्वपूर्ण दिलचस्पी देखने को मिली। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के लिए संभावित रूप से अपनाने और/या आवश्यकता आधारित उपयुक्त समाधान प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ■

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग

भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोग: संभावनाएं एवं चुनौतियां

आरआईएस और त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने 22–24 मार्च 2022 को अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला में संयुक्त रूप से 'भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोग : संभावनाएं एवं चुनौतियां' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

यह संगोष्ठी आरआईएस के मौलिक अनुसंधान क्षेत्रों में से एक पर आधारित थी। इसने भारत के अनुभवी और साथ ही साथ युवा शोधकर्ताओं, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों के युवा शोधकर्ताओं को एक उत्कृष्ट शैक्षणिक मंच प्रदान किया, ताकि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने आवास से संबंधित मुद्दों और सभी पड़ोसी देशों के साथ विकास साझेदारी पर अपने शोध अध्ययनों को साझा कर सकें। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत, बांग्लादेश और नेपाल के विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह संगोष्ठी ओएनजीसी द्वारा भी समर्थित थी।

इस संगोष्ठी में विकास सहयोग और पड़ोसी देशों के साथ भारत की विकास साझेदारी से संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों को रेखांकित किया गया। आरआई.ईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने प्रमुख भाषण में क्षेत्रीय संपर्क और पड़ोसी देशों के साथ व्यापक विकास सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने हाल के दिनों में भारत और पड़ोसी देशों द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। मोहिबुल हसन चौधरी, सांसद, शिक्षा उप मंत्री, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य ने दूसरा प्रमुख भाषण देते हुए कहा, "बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान त्रिपुरा–भारत का योगदान आज तक उल्लेखनीय है।" इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में युवा विद्वानों और पीएचडी के छात्रों ने भाग लिया। ■

बिम्सटेक में खाद्य और कृषि व्यापार

आरआईएस–आईएफपीआरआई राष्ट्रीय साझेदारों की बैठक 30 मार्च 2022 को आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के संबंध में बिम्सटेक द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया गया। बिम्सटेक दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है और रहेगा, हालांकि अधिकांश बिम्सटेक देशों के कृषि क्षेत्रों का अब तक लाभ नहीं उठाया गया है। खाद्य और कृषि व्यापार 1995 से वास्तविक रूप से दोगुना होकर 2018 में 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। आश्चर्यजनक रूप से, उभरते हुए और विकासशील देश वैश्विक व्यापार के एक–तिहाई भाग के लिए उत्तरदायी हैं। बिम्सटेक बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, परीक्षण के मानकों, विपणन और लॉजिस्टिक्स संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता पर चर्चा करेगा। बिम्सटेक देशों से होने वाले खाद्य निर्यात में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में, यह पिछले रुझान को उलटते हुए, नेपाल में हुए कुल व्यापारिक माल के निर्यात का 45.3 प्रतिशत था। यदि यही सिलसिला बरकरार रहा, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिम्सटेक कृषि पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में बल दे रहा है और इसे विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। व्यापार सुविधा, व्यापार वित्तपोषण, सीमा पार भुगतान का निपटान, और अन्य कारक खाद्य और कृषि क्षेत्रों को फलने–फूलने में सहायता कर सकते हैं।

प्रतिभागियों ने बिम्सटेक लिंकेज, साझेदारियों और सहयोग के वैचारिक ढांचे पर विचार–विमर्श किया। आर्थिक आघातों, जलवायु परिवर्तन और देशों के बीच टकराव के कारण गरीबी और खाद्य असुरक्षा; गरीबी का बढ़ता अनुपात; बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के कारण कम कमाई, बिम्सटेक की कुछ चुनौतियां हैं जबकि प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत तथा व्यापार और निवेश लाभ इसकी कुछ ताकतों में शामिल हैं। म्यांमार एकमात्र बिम्सटेक देश है जो कृषि में अग्रणी है। भारत पर्यटन, परिवहन, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद से निपटने में अग्रणी है। इसी तरह, प्रत्येक बिम्सटेक देश में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लिंकेज (एकीकृत फ्रेमवर्क) में अग्रणी क्षेत्र हैं। बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग के कुछ क्षेत्र हैं – जलवायु के अनुकूल एफटीए का कार्यान्वयन और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की सीमा, पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं में कमी, व्यापार और निवेश लाभ के लिए घरेलू नीति की आवश्यकता, आदि। इसका अंतिम लक्ष्य साक्ष्य–आधारित नीतिगत अंतर्दृष्टि तैयार करना है।

वैसे तो बिम्सटेक का क्षेत्रीय मॉडल अन्य क्षेत्रीय समझौतों से अलग है, लेकिन इसकी तुलना आसियान और दक्षेस (सार्क) से की गई है। दक्षेस के सदस्य देश बिम्सटेक के भी सदस्य हैं, इसलिए

...शेष पृष्ठ 9 पर जारी

जी–20

जी–20 में महिलाओं के मुद्दे और सफलता की राह

आरआईएस ने 8 मार्च 2022 को महिला दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में 'जी–20 में महिलाओं के मुद्दे और सफलता की राह' विषय पर एक विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया। डॉ नम्रता पाठक, परामर्शदाता, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया और पैनल चर्चा का संचालन सहायक प्रोफेसर डॉ पंखुड़ी गौड़ ने किया। इस चर्चा में प्रोफेसर पैम राजपूत, डिपार्टमेंट कम सेंटर फॉर वूमेंस स्टडीज एंड़ डेवलपमेंट, पंजाब विश्वविद्यालय प्रोफेसर लेखा एस चक्रवर्ती, राष्ट्रीय सार्व. जनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआइ. 'पीएफपी)य और डॉ बीना पांडे, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस मुख्य पैनलिस्ट थे। प्रारंभ में, प्रोफेसर चक्रवर्ती ने सार्वज. निक नीति में जेंडर को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक नीति दोनों ही महिला–पुरुष समानता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका यह भी विचार था कि महामारी के दौरान आर्थिक वृद्धि को रिकवर करने की प्रक्रिया के अंतर्गत बजटीय और मौद्रिक नीतियों में महिलाओं से जुड़े सरोकारों को शामिल किया जाना चाहिए। जी–20 फोरम में वित्त मंत्रालय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक कल्याण के रूप में मानव विकास और महिला–पुरुष समानता को वित्तपोषित करने का एक विशेष मंच है। जी–20 देशों में जेंडर बजटिंग महिलाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने का एक आशाजनक फ्रेमवर्क है।

प्रोफेसर पैम राजपूत ने अपनी प्रस्तुति में जी–20 में महिलाओं के मुद्दों के बारे में जानकारी दी और इस बात पर प्रकाश डाला कि डब्ल्यू–20 ने सभी देशों से अनुरोध किया है कि वे 2025 तक श्रम बल भागीदारी दर में जैंडर गेप को कम करने के लिए जी–20 द्वारा निर्धारित '25 बाय 25' के लक्ष्य की दिशा में नीतियों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह उन

डॉ बीना पांडे, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस

डॉ पंखुड़ी गौड़, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस

डॉ नम्रता पाठक, परामर्शदाता, आरआईएस

प्रोफेसर पैम राजपूत, विभाग सह महिला अध्ययन और विकास केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय

प्रतिबद्धताओं में से एक है, जिसे अभी तक अनेक जी–20 देशों में हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने श्रम, वित्त, जेंडर बजटिंग और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर जोर देते हुए जी–20 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों की प्रतिबद्धताओं पर बल दिया।

डॉ बीना पांडे ने जी–20 के बारे में आरआईएस के कार्यकलापों से संबंधित कार्यक्रम की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बतायी और जी–20 देशों में महिलाओं के मुद्दों के बारे में चर्चा की। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने बताया कि डब्ल्यूईएफ की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, प्रगति की वर्तमान दर के आधार पर महिला–पुरुष समानता हासिल करने में 100 साल का समय और लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं विभिन्न प्रकार की जिम्मेदा. रियों को साझा करने, अपने बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, और परिवार की आय में सहयोग देने, देखभाल से जुड़े अवैतनिक कार्य करने, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और आश्रितों आदि की देखभाल करने के अलावा, राष्ट्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी योगदान देती आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है। इनके अलावा, जी–20 देशों की सरकारों को महिलाओं की सामाजि. क–आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए सार्वजनिक, निजी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की निकट साझेदारी में प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए।

पैनल चर्चा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ। डॉ पंखुड़ी गौड़ ने सभी पैनलिस्टों और प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। ■

जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक सार्वजनिक सामान

आरआईएस ने ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव, जर्मनी के सहयोग से 18 फरवरी 2022 को जी–20 फाइनेंस ट्रैक के भाग के रूप में 'जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक सार्वजनिक सामान' विषय पर एक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया। इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय की वित्तीय नीति एजेंसी के अध्यक्ष श्री फेब्रियो नाथन काकारिबू ने इसमें उद्घाटन भाषण दिया। पहले पूर्ण सत्र में, राजदूत अभय ठाकुर, अपर सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय और जी–20 सोर–शेरपा द्वारा विशेष संबोधन किया गया। इसमें दो वक्ताओं : डॉ राजा अल मरजोकी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, अर्थव्यवस्था और नियोजन मंत्रालय, सऊदी अरब और रिध्दा विराकुसुमा, अध्यक्ष, बी20 इंडोनेशिया, वित्त और अवसंरचना कार्यबल ने भाग लिया। इसमें चर्चा करने वालों में डॉ इरिना करापेत्यांत्स, निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस, रशियन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट तथा क्रिश्चियन वर्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस और निदेशक, पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशंस, स्विसरे शामिल थे।

दूसरे पूर्ण सत्र का संचालन डॉ. निकोलस जे.ए. बकॉड, सह–अध्यक्ष टी20 इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स ने किया। चर्चा करने वालों में डॉ फ्रांसेस्को प्रोफुमो, अध्यक्ष, फोंडाजियोन कॉम्पेनिया डि सैन पाओल और पूर्व प्रमुख सह–अध्यक्ष, टी20 इटली इन्फ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्सय ओईसीडी में वरिष्ठ अर्थशास्त्री और टी20 इंडोनेशिया टीएफ8 रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग के सह–अध्यक्ष डॉ रैफेले डे ला क्रोस, और डॉ सेबेस्टियन वेनजेस, ग्लोबल पब्लिक गुड्स, जीआईजेड के लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के प्रोजेक्ट लीड, प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती, रिसर्च फेलो, आरआईएसय डॉ.यानिक ऑट्रेट, सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, फ्रांस के पारिस्थितिकी परिवर्तन मंत्रालय शामिल थे। समापन भाषण इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय के श्री सुदार्तो ने दिया। ■

बिम्सटेक में खाद्य और कृषि व्यापार

...शेष पृष्ठ 7 से जारी

दक्षेस से सबक सीखे जा सकते हैं। नेपाल के विपरीत, जहां किसान बेहद वंचित हैं और उनका पक्ष भी नहीं सुना जाता, भारत की नीतियां किसानों पर केंद्रित हैं। भारत किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। कृषि व्यापार घाटा ऐसे देश के लिए खतरनाक है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में चावल का बड़ा निर्यातक हुआ करता था।बांग्लादेश ने कृषि में काफी प्रगति की है और अब वह खाद्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। कृषि एक वैविध्यपूर्ण उद्योग है जिसमें अद्वितीय चुनौतियां हैं। कृषि में मूल्यवर्धन कठिन है। साथ ही, व्यापार और उद्योग से अलग–थलग रहते हुए कृषि का विकास नहीं किया जा सकता। कुछ परिस्थितियों में जीडीपी को 1.6 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एनटीबी के उन्मूलन को दिखाया गया है। टैरिफ उदारीकरण अन्य देशों की टैरिफ व्यवस्थाओं पर गौर किए बिना अधूरा है। बिम्सटेक देश व्यापारिक बाधाओं को दूर करके और संपर्क में सुधार करके एक सक्षम वातावरण बना सकते हैं। बिम्सटेक खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की समृद्धि, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में योगदान दे सकता है। ■

भारत–अफ्रीका साझेदारी

एनआईपीएल द्वारा डिजिटल भुगतान का प्रस्ताव

आरआईएस में जीडीसी ने सेंट्रल बैंक ऑफ मोजाम्बिक से संबद्ध एक सरकारी संस्था सोसाइडेड इंटरबेनकारिया डि मोकाम्बिक (एसआईएमओ) से संपर्क किया। यह संस्था देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के नियामक के रूप में कार्य करती है। एसआईएमओ के आदेश के तहत, यह मोजाम्बिक में डिजिटल भुगतान का प्रबंधन करती है। जीडीसी ने फरवरी 2022 में एसआईएमओ और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के प्रतिनिधियों के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय सत्र का आयोजन किया था। इसके बाद, जीडीसी ने 11 मार्च 2022 को विचार–विमर्श के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (यूएनआईडीओ) और एनआईपीएल के बीच द्विपक्षीय सत्र की मेजबानी की।

रिजर्व बैंक ऑफ मलावी के प्रतिभागी एनआईपीएल के साथ द्विपक्षीय सत्र में भाग ले रहे हैं।

दोनों सत्रों का उद्देश्य एनआईपीएल और मोजाम्बिक में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले विशिष्ट समाधानों का विवरण प्रदान करना है। एसआइ.एमओ और यूएनआईडीओ, मोजाम्बिक दोनों के हितधारकों ने भारत से डिजिटल भुगतान समाधान ग्रहण करने में काफी दिलचस्पी दिखाई। ■

को–विन टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर भारत–दक्षिण सूडान द्विपक्षीय सत्र

आरआईएस में जीडीसी ने 5 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय, के प्रतिनिधियों के बीच एक द्विपक्षीय सत्र का आयोजन किया। दक्षिण सूडान के प्रतिनिधियों और एनएचए के बीच यह व्यापक तकनीकी आदान–प्रदान का अवसर था। दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अपने देश में वर्तमान में उपयोग में लाई

...Continued on page 15

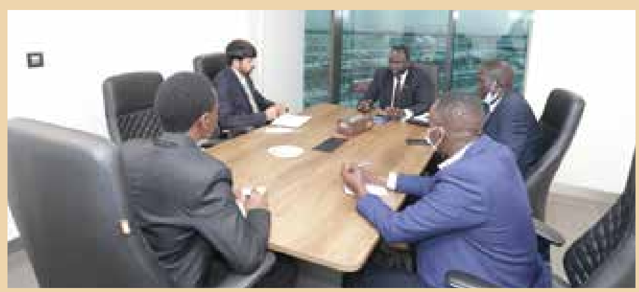

दक्षिण सूडान के प्रतिभागी द्विपक्षीय सत्र के दौरान एनएचए अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं।

डिजिटल भुगतान पर भारत–मलावी द्विपक्षीय सत्र

आरआईएस में जीडीसी ने एनआईपीएल और रिजर्व बैंक ऑफ मलावी के बीच एक द्विपक्षीय सत्र के आयोजन को सुगम बनाया। सत्र की अध्यक्षता आरआईएस शासी परिषद के सदस्य डॉ शेषाद्री चारी ने की। यह द्विपक्षीय सत्र मलावी के स्थानीय संदर्भों के आधार पर वहां की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में गहन तकनीकी आदान–प्रदान का एक अवसर था।

सत्र के दौरान, मलावी की टीम ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों की ओर कदम बढ़ाने के संबंध में अपने देश की योजना का विवरण प्रस्तुत किया तथा यूपीआई और रुपे कार्ड के साथ भारत के अनुभव के आधार पर अनुभव साझा करने और एक–दूसरे से सीखने की क्षमता की सराहना की। उन्होंने इस तरह की प्रणाली को लागू करने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ मलावी की प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। दूसरी ओर, एनआईपीएल की टीम ने विस्तृत तकनीकी विवरण, कार्यान्वयन और परिचालन के तौर–तरीकों, वित्त पोषण की व्यवस्था आदि प्रस्तुत किए और मलावी प्रतिनिधिमंडल द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके अलावा संचालन संबंधी लागत, क्षमता निर्माण की आवश्यकताएं सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। एनआईपीएल टीम और मलावी प्रतिनिधिमंडल ने अपने संपर्क के अगले चरणों पर भी सहमति व्यक्त की। ■

को–विन टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर भारत–इथियोपिया द्विपक्षीय सत्र

इथियोपिया के प्रतिभागी द्विपक्षीय सत्र के दौरान एनएचए अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं।

आरआईएस में जीडीसी ने 5 मार्च 2022 को स्वास्थ्य मंत्रालय, इथियोपिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक द्विपक्षीय सत्र का भी आयोजन किया। डॉ मेसेरेट जेलालेम के नेतृत्व में इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान में अपने देश में इस्तेमाल होने वाली जिला स्वास्थ्य सूचना (डीएचआई–2) प्रणाली को आगे बढ़ाने के प्रति इथियोपिया की दिलचस्पी व्यक्त की। उन्होंने सी–19 और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों, दोनों के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रति अपनी दिलचस्पी दोहराई। इस बात पर भी बल दिया गया कि एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जिसे इंटरऑपरेबल कार्य के लिए उनकी वर्तमान प्रणालियों के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का भी आह्वान किया।

एनएचए के प्रतिनिधि ने इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ काम करने के प्रति अत्यधिक दिलचस्पी व्यक्त की। इस संबंध में, को–विन प्रणाली से जुड़े तकनीकी विवरण साझा किए गए, जो इथियोपियाई प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई रिपोर्टिंग संबंधी चुनौतियों को दूर करेंगे। सहमत को–विन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दाता संगठनों के साथ एनएचए की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया। दोनों पक्षों ने संपर्क बनाए रखने पर सहमति प्रकट की। ■

एनआईपीएल द्वारा डिजिटल भुगतान के प्रस्ताव पर रवांडा के साथ द्विपक्षीय सत्र

जीडीसी ने सह–शिक्षण और डिजि. टल भुगतान के क्षेत्र में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, भारत द्वारा प्रदान किए गए उचित प्रस्तावों को उपयुक्त रूप से अपनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नेशनल बैंक ऑफ रवांडा के साथ संबंध स्थापित किए हैं। रवांडा की टीम को 5–6 मार्च 2022 को एक्सपो 2020, दुबई में कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। दुर्भाग्यवश कोविड–19 की वजह से यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के कारण उन्होंने एक्सपो में स्वयं भाग न लेकर वर्चुअल सत्र में शामिल होने को ज्यादा बेहतर समझा। रवांडा का नेतृत्व नेशनल बैंक ऑफ रवांडा की पेमेंट सर्विसिज के निदेशक श्री करमुका बगिरिश्य जॉन ने किया। इस कार्यक्रम में एनआईपीएल की डिजिटल भुगतान से संबंधित पेशकशों को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2022 को आयोजित किए गए इस वर्चुअल सत्र की नेशनल बैंक ऑफ रवांडा के अधिकारियों ने भरपूर सराहना की। ■

भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करने पर वेबिनार

आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 18 फरवरी, 2022 को पहला वेबिनार ' भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना' विषय पर वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। महामहिम राजदूत श्री अनग शॉन, कंबोडिया दूतावास, नई दिल्ली और राजदूत जयंत एन खोबरागड़े, आसियान में भारत के राजदूत, आसियान में भारतीय मिशन, जकार्ता ने विशेष भाषण दिए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, नई दिल्ली ने उद्घाटन भाषण दिया। भारत की हिंद–प्रशांत महासाग. रीय पहल (इंडो–पेसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव) और हिंद–प्रशांत पर आसियान का दृष्टिकोण, हिंद–प्रशांत में शांति और सुरक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हाल के अकादमिक और नीतिगत विमर्शों में हिंद–प्रशांत पर बहुत चर्चा हुई है और यह भ. ारत की विदेश नीति के निरुपण में इसकी प्रासंगिकता को बताता है। हिंद–प्रशांत में भारत की ओर से हाल में की गई पहल विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और विकास की निरंतरता के लिए उसकी स्थिति को दर्शाती हैं। हिंद–प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शीत युद्ध के बाद के दौर की विशेषताओं का प्रतीक है और बहुपक्षीय रचनावाद की प्रासंगिकता दर्शाता है। वेबीनार के अंत में डॉ प्रबीर डे ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

भारत–प्रशांत संवाद

भारत–आस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीपसमूह विकास सहयोग को आगे बढ़ाना

द एशियन फाउंडेशन और आरआईएस की ओर से ''एडवांसिंग साउथ–साउ. थ कोऑपरेशनः इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज'' के 2021 के प्रकाशन और आस्ट्रेलियाई विदेश एवं व्यापार विभाग (डीएफएटी) के समर्थन के बाद, 'भारत–आस्ट्रेलिया–प्रशांत द्वीपसमूह विकास सहयोग को आगे बढ़ाना' विषय पर चिंतन के लिए 31 मार्च 2022 को वेबिनार आयोजित किया गया। भारत, आस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपसमूह देशों के वक्ताओं ने भारत–प्रशांत द्वीपसमूह देशों के बीच साझेदारी के इतिहास और संभावनाओं पर गौर किया और पीआईसी में आस्ट्रेलिया और भारत के हितों के संयोजन के बिंदुओं पर चर्चा की। वेबिनार ने प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में त्रिकोणीय सहयोग की संभावनाओं का विश्लेषण करने के लिए और अधिक अध्ययन किए जाने चाहिए। ■

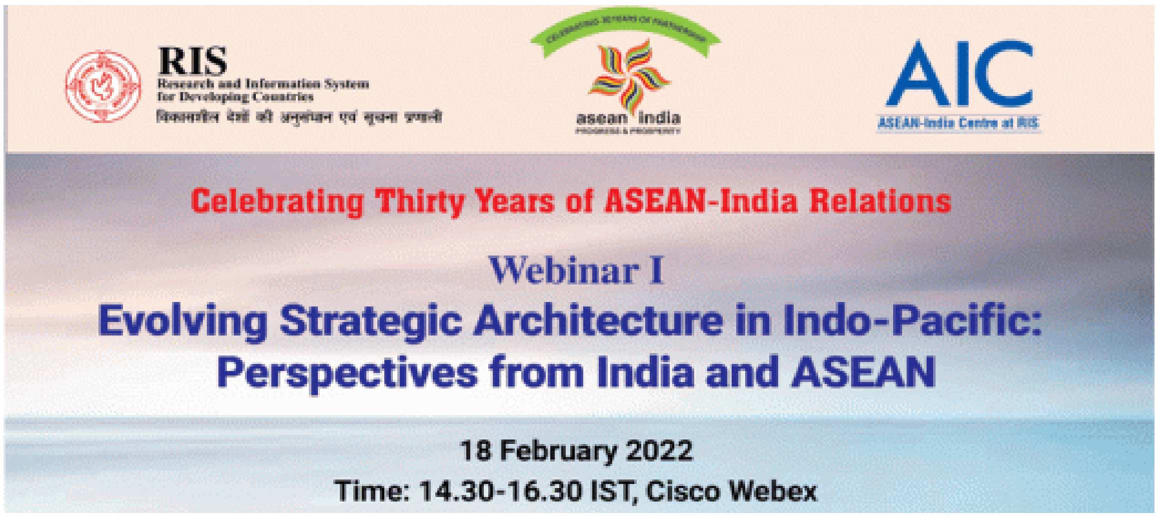

आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाना– भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना

1990 के दशक के आरंभ सें शुरू हुए वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वर्ष 2022 को आसियान–भारत मैत्री वर्ष नामित किया गया है। आसियान–भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, आरआईएस, आसियान–भारत संबंधों की अनवरत चुनौतियों और उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्चुअल मोड में वेबिनारों का आयोजन कर रहा है। आरआईएस साल भर आसियान–भारत संबंधों के पांच विषयगत क्षेत्रों पर पांच वेबिनार आयोजित करेगा। इसका प्रारंभ 18 फरवरी, 2022 को वर्चुअल माध्यम से आसियान–भारत संबंधों के रणनीतिक स्तंभ पर आधारित पहले वेबिनार के आयोजन से हुआ। यह वेबिनार 'भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना' विषय पर आयो. जित किया गया। डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी), आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने उद्‌घाटन भाषण दिया। महामहिम राजदूत श्री अनग शॉन, कंबोडिया दूतावास, नई दिल्ली और राजदूत जयंत एन खोबरागड़े, आसियान में भारत के राजदूत, आसियान में भारतीय मिशन, जकार्ता ने विशेष भाषण दिए। पैनल चर्चा की अध्यक्षता राजदूत राजीव भाटिया, विशिष्ट फेलो, गेटवे हाउस, मुंबई ने की। इसमें भाग लेने वाले वक्ताओं में सुश्री जोअ. ान लिन, प्रमुख शोधकर्ता, आसियान स्टडी सेंटर, आईएसईएएस यूसुफ–इशाक इंस्टी. ट्यूट, सिंगापुरय प्रो. राजाराम पांडा, सी. नियर फेलो, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल), नई दिल्लीय श्री वफा खरिश्मा, शोधकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंट. रनेशनल रिलेशंस (सीएसआईएस), जकार्ता और डॉ लॉरेंस प्रभाकर विलियम्स, प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान विभाग, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई शामिल थे। डॉ. संपा कुंडू, सलाहकार, आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी), आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

एसटीआईपी फोरम

'समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से ट्रांसलेशनल रिसर्च'

40वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान वैद्य श्री राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 फरवरी 2022 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय 'समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से ट्रांसलेशनल रिसर्च (यानी अकादमिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग में रुपांतरण) था। कार्यक्रम का संचालन डॉ. किंकणी दासगुप्ता मिश्रा, वैज्ञ. ानिक एफ, विज्ञान प्रसार ने किया।

वैद्य श्री राजेश कोटेचा ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा की जानकारी और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की प्राप्ति में पारंपरिक चिकित्सा द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारशील संबोधन की शुरुआत की। वैद्य श्री कोटेचा ने आयर्वुेद के माध्यम से ट्रांसलेशनल दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए इस बारे में विस्तार से समझाया कि किस प्रकार समस्त आयुर्वेद प्रणाली अपने आप में एक व्यव. स्थित ट्रांसलेशनल मॉडल है। आयुर्वेदिक ज्ञान प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना में 'तत्व' (सिद्धांत), 'शास्त्र' (सैद्धांतिक निर्माण ा) और 'व्यवहार' (व्यावहारिक अनुप्रयोग)

वैद्य श्री राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार।

शामिल हैं और इसका उद्देश्य अकादमिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग में रूपांतरण सुनिश्चित करना है। आयुर्वेदिक ज्ञान प्रणाली भी विज्ञान, तर्क और अनुभव के माध्यम से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है।

वैद्य श्री कोटेचा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और कार्यक्रमों की मुख्यधारा में आयुष को सम्मिलित करने के कुछ सफल उदाहरण साझा किए। उन्होंने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), सुप्रजा पहल जैसे राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल (आरसीएच) कार्यक्रम, वायु मित्र के माध्यम से जराचिकित्सा, प्रशामक सेवाओं (कारुण्य) में आयुष को सम्मिलित करने के मामलों को रेखांकित किय. ा। वैद्य श्री कोटेचा ने 75,000 स्कूलों में आयुष प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में आयुष मंत्रालय की ओर से की गई एक नई पहल आयुर्विद्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने महामारी के दौरान देश भर में कोविड–19 पर किए गए व्यापक आयुष अनुसंधानों की सूची भी साझा की।

अंत में, वैद्य श्री राजेश कोटेचा ने सफलता की राह के रूप में कुछ प्रमुख संकेतक भी प्रस्तुत किए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ अधिक अंतर्विषयक सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययनों को सुगम बनाने, एक राष्ट्रीय आयुष अनुसंधान संघ की परिकल्पना करने, उद्योग–अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा साक्ष्यों और अनुभवों को व्यवहार में रूपांतरित करने के लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए सहज ज्ञान या इंट्यूशनल व्यवस्था कायम करने का आह्वान शामिल था। ■

वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना : विश्व में भारत

41वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 28 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंध ान के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय 'वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना : विश्व में भारत' था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टेरी की महानिदेशक डॉ. विभा धवन ने की। स्वागत भाषण डॉ. भास्कर बालकृष्ण ान, विज्ञान कूटनीति, आरआईएस द्वारा दिया गया। उसके बाद इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने संक्षिप्त भाषण दिया।

...शेष पृष्ठ 15 पर जारी

एसटीआईपी फोरम व्याख्यान जारी है।

एफआईटीएम

'आयुष क्षेत्र को प्रोत्साहन : वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए उत्पाद श्रेणियों की पहचान'

आयुष मंत्रालय ने भारत को वैश्विक क्षमता और पैठ के साथ आयुष उत्पादों के विनिर्माण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं और वह कई उपक्रमों पर काम कर रहा है। घरेलू क्षमता और निर्यात बढ़ाने तथा भारत को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाने, आयात पर निर्भरता घटाने और घरेलू स्तर पर निर्मित आयुष उत्पादों की लागत में कमी लाते हुए उन्हें किफायती बनाने की रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है।

आरआईएस में एफआईटीएम ने उद्योग जगत के नीतिगत समर्थन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण घटकों की पहचान करने की दृष्टि से उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। 'आयुष क्षेत्र को प्रोत्साहनः वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए उत्पाद श्रेणियों की पहचान' विषय पर वर्चुअल गोलमेज चर्चा

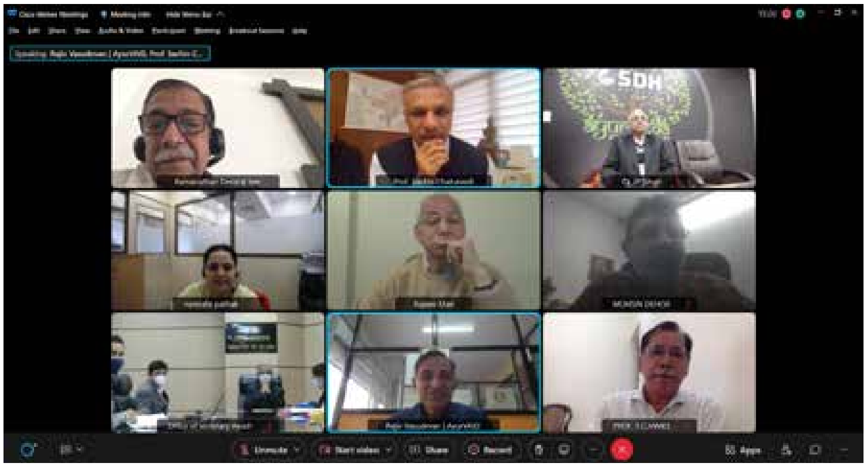

वेबिनार जारी है।

14 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसमें आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने उद्घाटन भाषण दिया। वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए आयुष उत्पादों की श्रेणियों पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो, आरआईएस, नई दिल्ली ने की और धन्यवाद ज्ञापन डॉ नम्रता पाठक, परामर्शदाता, आरआईएस, नई दिल्ली ने दिया। ■

एफआईटीएम की ओर से 'वन वर्ड वन हैल्थ' पर आमंत्रित व्याख्यान श्रृंखला

एफआईटीएम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विषय के विशेषज्ञों द्वारा आयुष प्रणाली के विकास और उसकी वैश्विक संबद्धता के बारे में अपने विचारों और अनुभवों पर मंथन किए जाने के उद्देश्य से आमंत्रित व्याख्यान श्रृंखला आरंभ की है। पहला आमंत्रित व्याख्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार द्वारा 16 फरवरी 2022 को 'वन वर्ड वन हैल्थ' विषय पर दिया गया। इस अवसर पर आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने की। प्रो. कुमार ने अपने व्याख्यान में वन हैल्थ के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक मूलभूत कदमों के रूप में एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोण सहित बीमारियों के जल्द निदान, आंकड़ों के सृजन और उन्हें सार्वजनिक

वेबिनार जारी है।

क्लाउड सिस्टम के माध्यम से साझा करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने मवेशियों के साथ ग्रामीण आबादी और समुदायों की व्यापक संबद्धता के कारण पशुओं के रोगों के प्रति उनकी अरक्षितता पर विचार करते हुए विशेष रूप से 'वन हैल्थ वन वर्ल्ड' रणनीति की आवश्यकता का समर्थन किया। उन्होंने पशुओं से इंसानों को होने वाली बीमारियों के निदान और रोकथाम में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के सामर्थ्य को देखते हुए वन हैल्थ के लिए इनके महत्व पर जोर दिया और आधुनिक चिकित्सा के साथ इसके प्रमाणीकरण पर बल दिया। आरआईएस में विजिटिंग फेलो, प्रो. टी.सी. जेम्स ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस व्याख्यान में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान आदि के कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। ■

इंडो–जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग, 2022

आरआईएस ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआइ. जीए), जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स (एसडब्ल्यूपी) के साथ संयुक्त रूप से 24 फरवरी को इंडो–जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग, 2022 का आयोजन किया। इस अवसर पर आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और जीआईजीए की अध्यक्ष प्रो अमृता नार्लीकर ने स्वागत भाषण दिया। विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ टोबियास लिंडनर ने उद्घाटन भाषण दिया। विदेश और सुरक्षा नीति पर सत्र–1 का संचालन एसडब्ल्यूपी के डॉ मार्कस कैम ने किया। वक्ता थेः पूर्व भारतीय राजदूत, आईसीडब्ल्यूए में पूर्व भारतीय राजदूत गुरजीत सिंह और जीआईजीए के उपाध्यक्ष प्रो डॉ पैट्रिक कोलनर। सत्र 2ः सतत विकास और व्यापार, का संचालन जीआईजीए के प्रो डॉ जेन ले ने किया और वक्ताओं में डॉ प्रियदर्शी दाश, आरआईएस, स्वेंजा शॉनिच, एसडब्ल्यूपी शामिल थे। आईसीडब्ल्यूए के महानिदेशक राजदूत विजय ठाकुर सिंह और एसडब्ल्यूपी के निदेशक डॉ स्टीफन मैयर ने समापन भाषण दिया। ■

को–विन टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर भारत–दक्षिण सूडान द्विपक्षीय सत्र

...शेष पृष्ठ 10 से जारी

जाने वाली प्रणाली की तुलना में अधिक क्षमताओं से युक्त डिजिटल प्रणाली ग्रहण करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण रूप से आंकड़ों की प्रविष्टि और उन्हें प्रॉसेस करने में सह. ायक प्रणालियों के प्रति दिलचस्पी व्यक्त की, जिसके लिए को–विन में सुनिश्चित संख्या है।

एनएचए के प्रतिनिधि ने दक्षिण सूडान की दिलचस्पी के अनुसार को–विन सिस्टम के पहलुओं को लागू करने की भारत की इच्छा साझा की। इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते एनएचए की ओर से अपार संभावित सहायता मौजूद है। प्रतिभागियों ने पास्परिक दौरों के आदान–प्रदान, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, आदि के माध्यम से संबद्धता बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ■

'वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना : विश्व में भारत'

...शेष पृष्ठ 13 से जारी

डॉ अजय माथुर ने अपने संबोधन में दु. निया और भारत में हो रहे ऊर्जा परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत इस बात को रेखांकित करते हुए की कि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर–जीवाश्म ईंधन ने बिजली उत्पादन मिश्रण का एक बड़ा भाग ले लिया है। वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 31 फीसदी है, जबकि भारत में यह 36 फीसदी है। भारत के लिए, यह इससे संबंधित पेरिस समझौते के लक्ष्य को अग्रिम तौर पर लगभग प्राप्त करने जैसा है। डॉ माथुर ने इतनी कम अवधि में इस तरह के महत्वपूर्ण बदलावों के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रेरक कारकों के बारे में विस्तार से बताया। इसका एक प्रमुख कारक नवीकरण ीय ऊर्जा की कीमतों में आई पर्याप्त गिरावट है। अन्य प्रमुख कारक बैटरी ऊर्जा भंडारण की लागत में कमी आना है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक निवेश में काफी वृद्धि हुई है और इसलिए इसकी संस्थापित क्षमताओं में भी वृद्धि हुई है।

डॉ माथुर ने दो प्रमुख सार्वजनिक नीतिगत हस्तक्षेपों अर्थात कीमत में कमी और मांग का सृजन– का उल्लेख करते हुए बताया कि ये भारत की सौर ऊर्जा स्थापना में वृद्धि करने में अब तक सहायक रहे हैं। फीड–इन टैरिफ और रिवर्स ऑक्शन वाली दो चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से कीमत में कमी हासिल की गई है, जबकि मांग का सृजन नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) की प्रणाली के माध्यम से हासिल किया गया। इन नीतिगत उपकरणों ने नवीकरणीय ऊर्जा की लागत को किफायती और प्रतिस्पर्धी बना दिया है, इस प्रकार उनके अधिक उपयोग को बढ़ावा मिला है। हालांकि, जैसा कि डॉ माथुर ने उल्लेख किया है, सोलर सेल और सौर मॉड्यूल के मामले में भारत का व्यापार संतुलन इस समय बेहद विरुपित है, जिसमें वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत में स्थापित केवल 36 प्रतिशत सौर पैनलों की आपूर्ति घरेलू निर्माताओं द्वारा की गई थी। डॉ. माथुर द्वारा इंगित एक अन्य चुनौती सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी की लागत के संदर्भ में है, जो कि अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे कई अन्य देशों की तुलना में भारत में काफी अधिक है। उन्होंने आशा प्रकट की कि हाल ही में शुरू की गई पीएलआई योजना निकट भविष्य में इस परिदृश्य में बदलाव लाने में सफल होगी। ■

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

- ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा 29 मार्च 2022 को आयोजित ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट में 'विकास सहयोग का भविष्य' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट।
- ग्लोबल सॉल्यूशन समिट 2022 में 29 मार्च 2022 को टी20 इंडोनेशिया 2022 द्वारा आयोजित 'उभरते देशों की परिवहन अधोसंरचना के विकास में डिजिटल परिवर्तन' विषय पर टास्क फोर्स8 टी 20 के कार्य सत्र में पैनलिस्ट।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा 29 मार्च,2022 को आयोजित ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट के दौरान जी–20/जी–7 में एजेंडा 2030 के प्रति नए तरीकों पर आयोजित साइड–इवेंट में 'टी/जी–7/20 में निवेश प्राथमिकताओं के बारे में भारत का परिप्रेक्ष्य' विषय पर प्रस्तुति दी।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा 29 मार्च 2022 को आयोजित ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट में 'विकास सहयोग का भविष्य' विषय पर प्रस्तुति दी।
- सेवा इंटरनेशनल द्वारा आपदा प्रबंधन पर 28 मार्च 2022 को आयोजित किए गए सम्मेलन में मुख्य वक्ता।
- कोरिया गणराज्य के साथ साझेदारी में यूएनआईडीओ और एसटीईपीआई द्वारा विकासशील देशों में नवाचार और औद्योगिकीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का क्षमता निर्माण विषय पर 22 मार्च 2022 को आयोजित किए गए ऑनलाइन वेबिनार में 'विकास के लिए नवाचार' पर प्रस्तुति।
- 21वीं साइंस काउंसिल ऑफ एशिया में आईसीएसएसआर द्वारा 15 मार्च 2022 को आयोजित 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान : बेहतर दुनिया के लिए एक साथ' विषय पर आयोजित सम्मेलन में सामाजिक–प्रौद्योगिकीय बदलाव और प्रमुख आर्थिक क्षेत्र' पर सत्र की अध्यक्षता की।
- वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) द्वारा 15 मार्च 2022 को आयोजित इंटरैक्टिव बैठक में 'आत्मनिर्भर भारत में एनबीएफसी की भूमिका : अवसर एवं चुनौतिया' पर प्रस्तुति दी।
- जीडीआई/डीआईई द्वारा 10 मार्च 2022 को आयोजित 'यूक्रेन में युद्धः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए निहितार्थ' विषय पर ऑनलाइन गोलमेज चर्चा में पैनलिस्ट।
- सीआईआई राष्ट्रीय समिति में 4 मार्च 2022 को आसियान और महासागरीय क्षेत्र पर 'हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए उभरते अवसर' पर प्रस्तुति दी।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (आईएससीएस) द्वारा 28 फरवरी 2022 को आयोजित 'बीबीआईएन कनेक्टिविटीः वे फॉरवर्ड' पर वेबिनार में 'बीबीआईएन कनेक्टिविटी' पर प्रस्तुति दी।
- मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी–आईडीएसए) द्वारा 24 फरवरी 2022 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति, आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और महिला–पुरुष समानता के बीच बढ़ते अंतर–संबंध पर विचारोत्तेजक सत्र में भाग लिया।
- मॉरीशस विश्वविद्यालय, विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, मॉरीशस तथा हिन्द महासागर तटीय सहयोग संघ(आईओआरए) सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से 24 फरवरी 2022 को आयोजित किए गए 'कोविड–19 के पश्चात अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए निरंतर नवाचार' विषय पर वर्चुअल विचारोत्तेजक कार्यशाला में 'डिजिटल स्वास्थ्य सेवा क्रांति' सत्र में मुख्य वक्ता।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा 23 फरवरी 2022 को आयोजित 'आर्कटिक में भारत की पहुंच का विस्तार' विषय पर इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया।
- भारत की आजादी के 75 वर्ष के समारोह के संदर्भ में 'यूरोपीय संघ–भारत के संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत में यूरोपीय संघ के नीति और आउटरीच प्रोजेक्ट द्वारा 22 फरवरी 2022 को आयोजित 'ईयू–इंडिया कनेक्टिविटी' पर वर्चुअल सत्र का संचालन किया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2022 को आयोजित 'लाइफ–जलवायु परिवर्तन से निपटने में जीवन शैली की भूमिका' पर विचारोत्तेजक बैठक में भाग लिया।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी 2022 को 'आयुष क्षेत्र संवर्धन : वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए उत्पाद श्रेणियों की पहचान' विषय पर आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग लिया।

- टी20 सचिवालय द्वारा 9 फरवरी 2022 को टी20 इंडोनेशिया 2022–स्थापना सम्मेलन में आयोजित 'वैश्विक स्वास्थ्य संरचना एवं वित्त पोषण' पर प्रस्तुति दी।
- मलयाला मनोरमा द्वारा 4 फरवरी 2022 को आयोजित 23वां मलयाला मनोरमा वार्षिक बजट प्रस्तुत किया।
- रवांडा कोऑपरेशन, एपीसी कोलंबिया और जर्मन डेवलॅपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से 19 जनवरी 2022 को साउथ–साउथ एंड ट्राइएंगुलर कोपरेशन का दोहनः सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान को कैसे बढ़ाया जाए' विषय पर आयोजित साउथ–साउथ एंड ट्राइएंगुलर कोपरेशन फोरम में 'ज्ञान साझा करने में परिचालन नवाचार : प्रभावी और निरंतर संचालन के उदाहरण' विषय पर सत्र का संचालन किया।
- ग्लोबल अलायंस फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस (एपीएआर), इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएलआरआई) और अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी (एयूडीए–एनईपीएडी) द्वारा संयुक्त रूप से 19 जनवरी 2022 को 'एक स्वास्थ्य सुरक्षाः अफ्रीका में पशु चिकित्सा एवं जूनोसिस रोगों के (पुनः)उभरने से बचावः एलएमआईसी में एक स्वास्थ्य रणनीति के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां और अवसर' में 'निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की राह की महत्वपूर्ण बाधाओं और अवसरों पर ध्यान देना' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में प्रस्तुति दी।
- टी20 सचिवालय द्वारा 17 जनवरी 2022 को टीएफ 8 के सह अध्यक्षों और विषयगत समन्वयकों के लिए आयोजित शुरुआती बैठक में स्थानीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास (पी ए–6) के प्रबंधन और वित्तपोषण पर टीएफ8 के सह–अध्यक्ष के रूप में भाग लिया।
- शिव नादर यूनिवर्सिटी (एसएनयू) द्वारा 5 जनवरी 2022 को सिनर्जेंस 2022– द नॉलेज वीक के दौरान आयोजित पैनल चर्चा में यूनिवर्सिटी थिंक–टैंक कनेक्ट–इनफेरेंस फॉर इंडिया–चाइना स्टडीज पर प्रस्तुति दी।

प्रोफेसर , l-d- ekgrh

- इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा स्थापित इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल (आईईआरए) अवार्डः 2020 में एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 21 मार्च 2022 को आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- मॉरीशस विश्वविद्यालय, विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, मॉरीशस तथा हिन्द महासागर तटीय सहयोग संघ(आईओआरए) सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से 23 फरवरी 2022 को आयोजित किए गए 'कोविड–19 के पश्चात अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए निरंतर नवाचार' विषय पर वर्चुअल विचारोत्तेजक कार्यशाला में 'आईओआरए में उभरती नीली अर्थव्यवस्थाः विनिर्माण ढांचे की बदलती गतिशीलता' विषय पर प्रस्तुति दी।
- टी20 सचिवालय, जकार्ता इंडोनेशिया की ओर से 10 फरवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्थापना सम्मेलन में 'वैश्विक व्यापार को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के बारे में पॉलिसी ब्रीफ : विकासशील देशों के लिए नीतिगत विकल्प' पर चर्चा में भाग लिया।
- 'वैश्विक व्यापार को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के बारे में टी20 पॉलिसी ब्रीफ : विकासशील देशों के लिए नीतिगत विकल्प' के बारे में 17 जनवरी, 2022 को नीतिगत सिफारिशें सौंपी और टी20 सचिवालय, जकार्ता इंडोनेशिया द्वारा 5 फरवरी, 2022 को उन्हें स्वीकार कर लिया गया।
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 2 फरवरी 2022 को आयोजित भारत–जीसीसी एफटीए पर संयुक्त कार्य समूह से संबंधित बैठक में भाग लिया।
- मध्य प्रदेश की निर्यात नीति 2022–2027 के प्रारूप पर चर्चा के लिए 10 जनवरी 2022 को लंच ऑन मीटिंग में भाग लिया।
- मध्यप्रदेश के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य–मध्य प्रदेश जीडीपी टास्क फोर्स पर योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 जनवरी 2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

एसोसिएट प्रोफेसर

- भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स द्वारा 14 जनवरी 2022 को आयोजित 'फिनटेक और डिजिटल

अर्थव्यवस्था के लिए एआई, साइबर जोखिमों और डेटा विज्ञान' विषय पर यूकेआईईआरआई–डीएसटी सम्मेलन में चर्चा में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया।

- जी–20 इंडोनेशिया द्वारा बी20 इंडोनेशिया, आरआईएस और ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव के सहयोग से 18 फरवरी 2022 को 'जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी ढांचा और वैश्विक सार्वजनिक सामान' विषय पर आयोजित वर्चुअल सेमिनार के दौरान चर्चा में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया।
- जी–20 इंडोनेशिया, टी20 इंडोनेशिया और यूएनआईडीओ द्वारा 24 मार्च, 2022 को 'जी–20 देशों में और उनके अलावा डिजिटीकरण और पर्यावरणीय निरंतरता को आगे बढ़ाने में उद्योग के महत्व' पर आयोजित रणनीतिक गोलमेज चर्चा में वक्ता के रूप में भाग लिया।

श्री राजीव खेर

विशिष्ठ फैलो

- आईसीआरआईईआर द्वारा 31 मार्च 2022 को आयोजित 'लचीली आपूर्ति श्रृंखला के प्रति भारत–जापान साझेदारी' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा 30 मार्च 2022 को आयोजित 'एशिया और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था : दृष्टिकोण और भावी जोखिम' विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईसीए और फिक्की द्वारा 19 मार्च 2022 को 'वैश्वीकरण के दौर में मध्यस्थता' विषय पर आयोजित सम्मेलन के चौथे संस्करण में भाग लिया।
- पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा 16 मार्च 2022 को आयोजित 'क्या हम एक ऐसा कार्बन टैक्स डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कारोबारी टकराव उत्पन्न न हों?' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- एशियन सेंटर फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा 18 फरवरी 2022 को आयोजित डायरेक्टर पावर ई–मीटिंग में भाग लिया।
- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 11 फरवरी 2022 को आयोजित चौथे वार्षिक सीनियर केयर कॉन्क्लेवः बिल्डिंग सिल्वर इकोनॉमी में भाग लिया।
- एयरटेल बैंक की 10–11 फरवरी 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा 9 फरवरी 2022 को आयोजित प्रमुख सेमिनार और बुक लॉन्च– द स्ट्रगल एंड द प्रॉमिसः रिस्टोरिंग इंडियाज पोटेंशियल में भाग लिया।
- गुडइयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 1 फरवरी 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 19 और 31 जनवरी 2022 को आयोजित अनुशासनात्मक समिति – बेंच– द्वितीय की बैठक में भाग लिया।
- 31 जनवरी 2022 को व्हिसल ब्लोअर पर प्री–बोर्ड मीटिंग में भाग लिया।
- संसद टीवी द्वारा 22 जनवरी 2022 को आयोजित व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने से संबंधित बजट स्पेशल इंग्लिश प्राइम टाइम शो में आमंत्रित किया गया।
- एयरटेल पेमेंट्स बैंक ड्राफ्ट रणनीति नोट पर 18 जनवरी 2022 को आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- 17 जनवरी 2022 को एनएबीसीबी सलाहकार समिति के मानद सदस्य के रूप में भाग लिया।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फैलो

- आईसीआरआईईआर द्वारा 31 मार्च 2022 को आयोजित 'लचीली आपूर्ति श्रृंखला के प्रति भारत–जापान साझेदारी' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- आरआईएस द्वारा द एशिया फाउंडेशन के सहयोग से 31 मार्च 2022 को भारत –ऑस्ट्रेलिया–प्रशांत द्वीपसमूह विकास सहयोग को आगे बढ़ाना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- किंग अब्दुलअजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर (इथरा), दहरान, सऊदी अरब द्वारा 30 मार्च 2022 को आयोजित 'डिजिटल वेलबीइंग' शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस द्वारा 28–29 मार्च 2022 को आयोजित 'विश्व की सुनेंः सार्वभौमिक सीमाओं के भीतर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना' पर शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- आरआईडीएस द्वारा विज्ञान प्रसार के सहयोग से 28 मार्च 2022 को न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मानद सचिव डॉ के

श्रीधर द्वारा 'रिवायरिंग द ब्रेनः इज इट पॉसिबल?' विषय पर दिए गए एसटीआईपी व्याख्यान में भाग लिया।

- 23 मार्च 2022 को आयोजित टीएफ5 बैठक में 'उत्तरजीविता के लिए शिक्षा– प्रारंभिक बचपन के लिए बहु–क्षेत्रीय और एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण को मजबूत करना' शीर्षक वाले पॉलिसी ब्रीफ के लिए सह–लेखक के रूप में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर–पीआरआई द्वारा 22 मार्च 2022 को 'भारत और जापान में कोविड–19 के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं और भविष्य में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- एशियन कॉन्फ्लुएंस, इंडिया ईस्ट एशिया सेंटर द्वारा 3 मार्च 2022 को 'पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र और पड़ोस का विकासः उद्यमिता और लोगों जोड़ने हेतु भारत–जापान सहयोग' विषय पर आयोजित वेब संवाद में भाग लिया।
- डॉ अजय माथुर, डीजी, आईएसए द्वारा 28 फरवरी 2022 को सौर ऊर्जा पर एसटीआईपी नीतिगत व्याख्यान में भाग लिया।
- आरआईएस, आईसीडब्ल्यूए, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए) और जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स (एसडब्ल्यूपी) द्वारा 24 फरवरी, 2022 को आयोजित इंडो–जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग 2022 में भाग लिया।
- टी20 सचिवालय, इंडोनेशिया द्वारा 24 फरवरी 2022 को आयोजित 'इंडोनेशिया जी–20 अध्यक्षता : आर्थिक परिवर्तन से एक साथ रिकवर करना और मजबूती से रिकवर करना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- ' आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाना – भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना' पर 18 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया।
- जी–20 इंडोनेशिया के साथ आरआईएस और ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव के सहयोग से 18 फरवरी 2022 को जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक सार्वजनिक सामान विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया।
- 9 और 10 फरवरी 2022 को आयोजित 'कोविड–19 महामारी से समावेशी रिकवरी को साकार करना' शीर्षक वाले टी20 स्थापना सम्मेलन में भाग लिया।
- आईएफएडी द्वारा 3 फरवरी 2022 को आयोजित 'ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2021ः खाद्य प्रणाली की मुख्यधाराएं' पर चर्चा में भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा 19 जनवरी, 2022 को आयोजित 'कृषि खाद्य प्रणालियों को आघातों और दबावों के प्रति अधिक लचीला बनाना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फैलो

- आईसीआरआईईआर द्वारा 31 मार्च 2022 को आयोजित (वर्चुअल) 'लचीली आपूर्ति श्रृंखला के प्रति भारत–जापान साझेदारी' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- किंग अब्दुलअजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर (इथरा), दहरान, सऊदी अरब द्वारा 30 मार्च 2022 को आयोजित 'डिजिटल वेलबीइंग' शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस द्वारा 28–29 मार्च 2022 को आयोजित 'विश्व की सुनेंः सार्वभौमिक सीमाओं के भीतर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना' पर हाइब्रिड शिखर सम्मेलन (वर्चुअल) में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर–पीआरआई द्वारा 22 मार्च 2022 को 'भारत और जापान में कोविड–19 के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं और भविष्य में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- टी20 सचिवालय, इंडोनेशिया द्वारा 24 फरवरी 2022 को आयोजित 'इंडोनेशिया जी–20 अध्यक्षता : आर्थिक परिवर्तन से एक साथ रिकवर करना और मजबूती से रिकवर करना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा 19 जनवरी, 2022 को आयोजित 'कृषि खाद्य प्रणालियों को आघातों और दबावों के प्रति अधिक लचीला बनाना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।

डॉ. पंखुड़ी गौड़

सहायक प्रोफेसर

- वाणिज्य विभाग में 9 मार्च, 2022 को आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- आईएसडीबी टीम के साथ 19 जनवरी, 2022 को एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया।

fjikVl

- 75 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट पार्टनरशिप –सागा ऑफ कमिटमेंट टू प्लूरेलिटी, डाइवर्सिटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस आरआईएस, नई दिल्ली, 2022
- लेवरेजिंग इंडियाज डिजिटल एक्सपीरियेंस इन पेमेंट्स एंड वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, जीडीसी, नई दिल्ली, 2022
- इंडिया–नाइजीरिया वेबिनार ऑन प्रोमोटिंग एमएसएमई टू एन्हेंस इंडस्ट्रीलाइज़ेशन : चैलेंजिस एंड प्रॉस्पे. क्ट्स, आरआईएस, नई दिल्ली, 2022
- वर्चुअल ब्रेनस्ट्रोमिंग सेशन टी20 रिफॉर्म्स फॉर अपकमिंग जी 20 डेवलपिंग कंट्री प्रेजीडेंसीज, आ. रआईएस, नई दिल्ली, 2022

vkjvkbl,l ppkl i=

#272: भारत में मूल निवासी होने का आशय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ
द्वारा टी सी जेम्स

#272: इंटरनेशनल डिस्कशन्स ऑन इन्डीजनस पीपुल एंड इंडिया,
द्वारा टी सी जेम्स

#271: रोल ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसो. सिएशन इन द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी इन प्री–इंडीपेंडेंस इंडिया द्वारा स्नेहा सिन्हा

,vkbl h 0;k[;k ¼dkeVh½ J`[kyk,

एआईसी कॉमेंट्री सं. 27, मार्च, 2022, हार्नेसिंग इंडिया–आसियान सिनर्जीज इन द इंडो–पे. सिफिक द्वारा अविनाश गोडबोले

एआईसी कॉमेंट्री सं. 26, फरवरी, 2022, एक्सप्. लोरिंग इंडियाज वे फॉरवर्ड फॉर ई–वीबीएबी पार्टनरशिप विद आसियान द्वारा संपा कुंडू, निदा रहमान और श्रेया पान

एआईसी कॉमेंट्री सं. 25, जनवरी, 2022, अनफो. ल्डिंग इंडिया–आसियान रिलेशन्स इन थर्टी इयर्स ऑफ जर्नी द्वारा पिनाक रंजन चक्रवर्ती

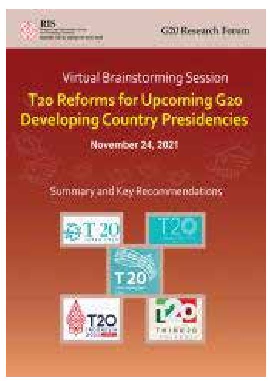

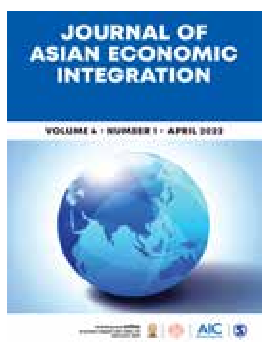

,vkbl h dk;l i=

एआईसी कार्य पत्र 9 शीर्षक 'एन्हेंसिंग आसियान–इंडिया पार्टनरशिप इन ई–वीबीएबी : चैलेंजिस, ऑपर्च्यूनिटीज एंड द वे फॉरवर्ड' द्वारा संपा कुंडू, निदा रहमान और श्रेया पैन

,vkbl h tuly % tuly vkQ ,f'k;u bdkukfed bVhxs'ku] वॉल्यूम 4, नं. 1

vkjvkbl,l ldk; }kjk ckg- jh ifdk'kuka ea ;kxnku

चतुर्वेदी, सचिन (2022)। देखिए : इंटरिम बजट इज ऑल अबाउट शॉर्ट–टर्म नीड्स एंड लॉन्ग–टर्म विजन, *द इकोनॉमिक टाइम्स,* 24 जनवरी, नई दिल्ली।

चतुर्वेदी, सचिन (2022)। 'यू एन्स 2030 एजेंडा इज लाइक सबका साथ सबका विकास' *ब्लिट्ज इंडिया,* 12 फरवरी, नई दिल्ली

चतुर्वेदी, सचिन (2022)। बजट 2022 गेव क्लीयर प्लान्स फॉर लॉन्ग–टर्म ग्रोथ : लेक्चर डिलिवर्ड ऐट मलयाला मनोरमा, *द वीक,* 04 फरवरी, 2022

चतुर्वेदी, सचिन (2022)। बिग गेन्स, हाई स्टेक्स इन बिम्सटेक, *द इकोनॉमिक टाइम्स,* 30 मार्च, 2022

डे प्रबीर 2022 । 'स्ट्रेंगथनिंग इकोनॉमिक रिलेशन्स विद आसियान : रोल दैट इंडिया एंड कोरिया कैन प्ले' इन क्वोन ह्यूंग ली एंड यून हाये रो (ईडीएस.) द न्यू सदर्न पॉलिसी प्लस : प्रोग्रेस एंड वे फॉरवर्ड, कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी (केआईईपी), सोल

डे प्रबीर 2022 । 'एसएएसईसी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स : चैलेंजिस एंड वे फॉरवर्ड' इन सीएआरईसी इंस्टीट्यूट (ईडी.) सीएआरईसी थिंक–टैंक्स फोरम रिपोर्ट 2021 : इकोनॉमिक कॉरिडोर्स सीएआरईसी इंस्टीट्यूट, उरुमची

डे प्रबीर 2022 । 'डिसाइफरिंग द इंडो–पेसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क' नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली

डे प्रबीर 2022 और अन्य 2022। 'एक्स–एंटी इवेल्यूएशन ऑफ इंडियाज ट्रेड एलाएंस विद इंडो–पेसिफिक : अ जनरल इक्वलिब्रीअम एनालिसिज' एआरटीएनईटी वर्किंग पेपर रु 211ए एआरटीएनईटी, यूएनईएससीएपी, बैंकाक

डे प्रबीर 2022 । 'विल द अपकमिंग बिम्सटेक समिट बी अ गेम–चेंजर' *हिंदु बिजनेस लाइन,* 25 मार्च, 2022

डे प्रबीर 2022 । 'टुवर्ड्स सीमलेस बॉर्डर कनेक्टिविटी इन साउथ एशिया' *डेली स्टार,* ढाका, 9 मार्च, 2022

रहमान,निदा और अन्य 2022। 'डू ट्रेड एंड पॉवर्टी कॉज ईच अदर? एविडेंस फ्रॉम ब्रिक्स' *ग्लोबल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज,* 14 (1), पीपी. 9–31

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर IV-B, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110 003, भारत। दूरभाष 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ईमेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः www.ris.org.in

हमें यहां फॉलो करें:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi